

478 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

[2023] 10 एस सी आर 478:2023 आईएनएससी 676 ए

ए.

पी. युवाप्रकाश बनाम

राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा (आपराधिक अपील सं.)।1898 2023 का) 18
जुलाई, 2023

बी.

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.]

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।3,4,5,6,7, 34 - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 -धारा 94-बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 -धारा 10-दंड संहिता, 1860 -s.366-के तहत बरी-अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी-आरोपी और अन्य लोगों ने पीड़ित 'एम' (कथित रूप से 17 वर्षीय लड़की) का अपहरण कर लिया-शिकायत यू/एस दर्ज की गई।366 भारतीय दण्ड संहिता सी. का ए-अपीलार्थी ने उसके साथ विवाह किया और यौन संबंध बनाए-एम का पुलिस द्वारा पता लगाया गया-दर्ज किए गए अपने बयान में, 'एम' ने कहा कि वह आरोपी को जानती थी और दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और स्वेच्छा से भाग गए थे-निचली अदालत ने अपीलार्थी और अन्य लोगों को दोषी ठहराया और उसे अन्य बातों के साथ-साथ यू/एस की सजा सुनाई गई।6 आजीवन कठोर कारावास से गुजरने के लिए पाँक्सो अधिनियम-उच्च न्यायालय ने पाँक्सो अधिनियम के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन उसकी सजा को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास कर दिया गया; उसे बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत भी दोषी ठहराया गया-अपीलार्थी को यू/एस के आरोप से बरी कर दिया गया।366 भारतीय दण्ड संहिता सी. का-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़, अर्थात्, एक हस्तांतरण प्रमाण पत्र और प्रवेश रजिस्टर के उद्धरण, एस के अधिदेश के अनुसार नहीं हैं।94(2)(i) जेजे अधिनियम और न ही वे एस के अनुरूप हैं।94(2)(ii) जेजे अधिनियम-इस प्रकार, साक्ष्य का एकमात्र टुकड़ा, एस के साथ दिया गया है।94 जेजे अधिनियम का मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट था और पीडब्लू-9 (जांच करने वाले डॉक्टर) ने राय दी कि पीड़ित 18-20 वर्ष के बीच था और प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-9 ने कहा कि उम्र 19 वर्ष हो सकती है-ऑसिफिकेशन या हड्डी परीक्षण का परिणाम सबसे प्रामाणिक सबूत था, जिसकी पुष्टि पीडब्लू-9 द्वारा की गई थी-पीड़ित यू/एस के बयान को ध्यान में रखते हुए।164 सी. आर. पी. सी., अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि अपीलार्थी की ओर से जबरदस्ती या मजबूरी के परिणामस्वरूप कोई भेदक यौन हमला हुआ था-अभियुक्त यू/एस के खिलाफ आरोप।6 पाँक्सो अधिनियम के साथ-साथ एस।10 बाल विवाह निषेध अधिनियम को कायम नहीं रखा जा

सकता-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया और अपीलार्थी को बरी कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

478

479

पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक ए द्वारा

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: **1.** यह स्पष्ट है कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज ने "जन्म तिथि" के विवरण का उत्तर नहीं दिया।

स्कूल से प्रमाण पत्र "या" मैट्रिक या समकक्ष

संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्रमाण पत्र या निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के लिए स्वीकार्य चिकित्सा परीक्षणों/जांच के माध्यम से यह साबित करना अनिवार्य था कि जेजे अधिनियम की धारा **94 (2) (iii)** के अनुसार पीड़ित की आयु **18** वर्ष से कम थी। वेल्लोर के जनरल अस्पताल में मुख्य सिविल डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट पीडब्लू-**9** ने एक्स-रे रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि एम की जांच के संदर्भ में, एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि

बी.

सी.

उक्त लड़की की आयु **18** वर्ष से अधिक और **20** वर्ष से कम होगी।

बरसों "। जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया कि एम की उम्र को **19** वर्ष के रूप में लिया जा सकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया

साक्ष्य में कहा गया है कि "जब स्कूल के रिकॉर्ड से जन्म की सटीक तारीख उपलब्ध होती है, तो चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अनुमानित अनुमानित आयु निर्धारण कारक नहीं हो सकती है।" यह खोज

डी.

इस न्यायालय के माने गए दृष्टिकोण में, गलत और गलत है। जैसा कि पहले कहा गया था, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रवेश रजिस्टर के उद्धरण, वे नहीं हैं जो धारा **94 (2) (i)** अनिवार्य करती है; और न ही वे धारा **94 (2) (ii)** के अनुरूप हैं क्योंकि डी. डब्ल्यू.-1 ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि पीड़ित के जन्म से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं थे, एम. इन परिस्थितियों में, जेजे अधिनियम की धारा **94** के साथ दिया गया एकमात्र साक्ष्य चिकित्सा अस्थीकरण परीक्षण था, जो पीड़ित के कई एक्स-रे के आधार पर था, और जिसके आधार पर पीडब्लू-9 ने अपना बयान दिया था। उसने पीड़ित की हड्डियों की जांच, उनके विकास के चरण के बारे में विस्तार से बताया और राय दी कि वह **18-20** वर्ष के बीच थी; प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि उम्र **19** वर्ष हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, इस अदालत की राय है कि ऑसिफिकेशन या हड्डी परीक्षण का परिणाम सबसे प्रामाणिक सबूत था, जिसकी पुष्टि जांच करने वाले डॉक्टर, पीडब्लू-9 द्वारा की गई थी। [पैरा **19**] [488-एफ-एच; 489-ए-डी]

ई.

एफ.

जी.

2. सी. आर. की धारा 164 के तहत अपने बयान में। पी. सी., पीड़ित एम ने बयान दिया था कि वह अपीलार्थी से प्यार करती थी, उसने जहर खा लिया था, और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती भी हो गई थी क्योंकि वह अपीलार्थी के साथ रहने के लिए दृढ़ थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह पलट गई

एच.

480 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

उसके बयान से। फिर भी, चिकित्सा साक्ष्य (अभियोजन साक्षी-1-डॉक्टर का बयान) ने संकेत दिया कि पीड़ित के गुप्तांग में कोई बाहरी चोट नहीं थी, और उसके अनुसार

उसकी "चिकित्सा जांच से **48** घंटे पहले यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसने यौन उत्पीड़न किया था, यह मेरी राय है।"

इस गवाह ने अपने परीक्षण के नोट्स भी प्रस्तुत किए (उदा. पी-11)। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की राय है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि अपीलार्थी की ओर से जबरदस्ती या मजबूरी के परिणामस्वरूप कोई भेदक यौन हमला हुआ था। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी सजा को कम करते हुए इसे मान्यता दी (क्योंकि, उसकी राय में, एम उस समय नाबालिग था), यह देखते हुए कि "पी. डब्ल्यू. 3 ने कहा था कि

बी.

सी.

प्रेम विफलता के कारण आत्महत्या करने के लिए जहर लेने की हद तक, भारी दबाव में, वह पी. डब्ल्यू. 3 के साथ था, उससे शादी की और उसके साथ यौन संबंध बनाए, दोनों शादी से पहले भी।

शादी के बाद।" इन तथ्यों और पॉक्सो अधिनियम के तहत परिभाषाओं, विशेष रूप से "यौन हमले" की परिभाषाओं, धारा 5 और 6, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 350 और 351 के साथ पढ़ा जाता है, से यह देखा जा सकता है कि यह केवल तभी होता है जब भेदक यौन हमला होता है, जिसका अर्थ है नाबालिग पीड़िता की सहमति के साथ या उसके बिना यौन संपर्क, कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध किए जाते हैं। [पैरा 21] [491-ए-एफ]

डी.

ई.

ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [2021] 12 एससीआर 502; संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2019] 9 एससीआर 735 -

पर भरोसा किया।

अबुज़र हुसैन @गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम राज्य

एफ.

बंगाल [2012] 9 एस. सी. आर. 224-संदर्भित। मामला कानून संदर्भ

[2021] 12 एससीआर 502

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[2019] 9 एससीआर 735

उस पर भरोसा करें

पैरा **16 [2012] 9 एस. सी. आर. 224** पैरा **17** में निर्दिष्ट है।

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.1898।

2016 के सी. आर. ए. No.400 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2016 से।

एच.

481

पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक ए द्वारा

ए.

सुश्री ई. आर. सुमथी, एस. आनंद, शंकर गणेश आर., अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी. कृष्णमूर्ति, ए. ए. जी., डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री ऋचा विश्वकर्मा, सुश्री वैदेही रस्तोगी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. एकमात्र अपीलार्थी मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि और उसकी याचिका को अस्वीकार करते हुए दी गई सजा से व्यथित है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (इसके बाद "आई. पी. सी.") के तहत अपराध करने से बरी कर दिया गया है, लेकिन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (इसके बाद "पॉक्सो अधिनियम") की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया है। 2. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि एक व्यक्ति टी. अब्दुल हमीद ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी छोटी बेटी (इसके बाद "एम" या "पीड़ित"), जिसकी उम्र 17 साल (18 साल की है), को पेट दर्द था जब वह 13.01.2015 पर काम पर गया था। उनकी बड़ी बेटी वहीदा और उनकी छोटी बहन अमीना एम को अस्पताल ले गए थे। जब वे घर लौट रहे थे, लगभग 1 बजे रीटा स्कूल, शास्त्री नगर के पास, एक युवप्रकाश और दो अन्य मौके पर पहुंचे, एम का अपहरण कर लिया और वहां से दोपहिया वाहन से भाग गए। इस घटना की जानकारी अब्दुल हमीद को उनकी बड़ी बेटी ने फोन पर दी थी। उन्होंने और अन्य लोगों ने आस-पास के क्षेत्रों में एम की खोज की, लेकिन यह व्यर्थ रहा। अब्दुल हमीद ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 ए के तहत शिकायत दर्ज कराई। यह आगे आरोप लगाया गया कि 14.01.2015 पर, अपीलार्थी और

ए-3, ए-4, ए-6 से ए-9 तक एम को कोडुमुडी शहर के एक मंदिर में ले गए, जहाँ अपीलार्थी ने अपनी शादी को संपन्न करने के लिए एम के गले में एक थाली बांध दी। विवाह के बाद, फिर से अपीलार्थी और ए-3, ए-4, ए-6 से ए-9 एम को दूसरे अभियुक्त के घर ले गए, जहाँ उन्होंने उसे अपीलार्थी के साथ रहने के लिए कहा। यह आरोप लगाया गया था कि जब वे वहाँ थे, अपीलार्थी ने एम के साथ बार-बार यौन संबंध बनाए थे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

3. यह भी आरोप लगाया गया था कि 15.01.2015 पर, आरोपी एम को एक ओम्नी वैन में मदुरै ले गया, जहाँ अपीलार्थी 15 के बीच अपने चाचा के घर में उसके साथ रहा: 01.2015 और 25.01.2015, सीलनायकनपट्टी में और इस दौरान भी, अपीलार्थी ने बार-बार पीड़ित के साथ यौन संबंध बनाए। इस बीच, पुलिस ने शिकायत की जांच की, जिसे लापता व्यक्ति की रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया गया था। उस पर

जी.

1 सीआर में सामान्य अंतिम क्रम दिनांक 14.12.2016 द्वारा। ए. सं. 400/2016। 2 2015 के अपराध सं. 22 में दर्ज।

एच.

482

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

25.01.2015, अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों को पता चला कि एक शिकायत दर्ज की गई है; परिणामस्वरूप, उन्होंने एम को छोड़ दिया और मदुरै छोड़ दिया। इसके बाद वह इरोड में अपने पिता के घर लौटी, जब वह उसे पुलिस स्टेशन ले गया और जांच अधिकारी (आई. ओ.) को बताया कि क्या हुआ था। पीडब्लू-16। पीडब्लू-16 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (इसके बाद "दंड प्रक्रिया संहिता") के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया। पी. सी. ")। एम का बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। पीसी। इसमें, उसने कहा कि वह आरोपी को जानती थी, और दोनों एक-दूसरे से लगभग एक साल से प्यार करते थे; यह उसके पिता और दादी को पता था, जिन्होंने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी। इसके कारण उसने चूहे का जहर खाकर आत्महत्या कर ली; हालाँकि, उसे अस्पताल में भर्ती कराया

गया और उसका इलाज किया गया। उसने आगे कहा कि वह अपीलार्थी के साथ स्वेच्छा से भाग गई-एक तथ्य जो उसकी चाची और उसकी बहन पीडब्लू-4 को पता था। उसने यह भी कहा कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ उसकी शादी की, और वे एक विवाहित जोड़े के रूप में रहते थे। उसके अनुसार, जब वे एक साथ रह रहे थे, तो पुलिस उसकी तलाश में आई, जिसके बाद उसे पता चला कि उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आगे स्पष्ट किया कि उसका कभी अपहरण नहीं किया गया था और न ही जबरन शादी की गई थी और उसने अपनी इच्छा के अनुसार अपीलार्थी से शादी की थी।

बी.

सी.

डी.

4. एम का पता चलने के बाद, पुलिस ने शिकायत को बदल दिया; प्रथम सूचना रिपोर्ट में अब पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 17 के साथ-साथ अन्य अपराध, जैसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 10 शामिल हैं। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों (अर्थात्, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों, ए-2 से ए-9) पर आरोप पत्र में जिन अपराधों का आरोप लगाया गया था, उन्हें करने का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था; उन्होंने अपराध को छोड़ दिया और मुकदमे का सामना किया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन प्रमुख गवाहों पर भरोसा किया गया वे पीडब्लू-3 (पीडित, यानी, एम); पीडब्लू-4, उसकी बहन; पीडब्लू-5, जो शत्रुतापूर्ण हो गई; पीडब्लू 6, 7 और 8, जिन्होंने एक मोटरसाइकिल के संबंध में गवाही दी, कहा जाता है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा उधार ली गई थी। एम की जांच करने वाले डॉक्टर पीडब्लू-9 और पीडब्लू-11 थे। पीडब्लू-15, उप-निरीक्षक जिन्होंने मामला दर्ज किया और पीडब्लू-16, आईओ, जिन्होंने अनुसंधान पूरी की। निचली अदालत ने अपीलार्थी और अन्य लोगों को दोषी ठहराया; अपीलार्थी को अन्य बातों के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

ई.

एफ.

जी.

5. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा दोषसिद्धि को संशोधित किया। अभियुक्त ए 3, ए 4, ए 6 से ए 9 को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 10 के तहत दोषसिद्धि गया था; दूसरे अभियुक्त (ए 2) को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और अपीलार्थी को ए के तहत दोषसिद्धि गया था।

एच.

पी. युवप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

पाँक्सो अधिनियम की पुष्टि की गई थी लेकिन कठोर कारावास के साथ आजीवन कारावास की उनकी सजा को घटाकर 10 साल कठोर कारावास कर दिया गया था; उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 10 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 366 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया और सजा को दरकिनार कर दिया गया। 6. विद्वान अधिवक्ता सुश्री ई. आर. सुमथी ने प्रस्तुत किया कि नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्ष अस्थिर हैं। सबसे पहले, उसने इस परिस्थिति पर भरोसा किया कि पीड़ित एम ने धारा 164 Cr.PC के तहत अपने बयान में स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह अपनी मर्जी से अपीलार्थी के साथ चली गई और उसकी बहन और चाची इन तथ्यों को जानती थीं। यह इंगित किया गया कि वही कथन आगे स्वीकार करता है कि एम और अपीलार्थी एक-दूसरे को एक साल से जानते और प्यार करते थे। इन परिस्थितियों में, जब वह अपीलार्थी के साथ भाग गई, यह तथ्य कि उसने मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने पिछले बयान का समर्थन नहीं किया और उससे इनकार कर दिया, एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए था जो अभियोजन पक्ष की कहानी के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। 7. विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस संबंध में निचली अदालत का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था क्योंकि दर्ज किए गए निष्कर्ष यह हैं कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में असमर्थ था कि एम अपीलार्थी के किसी दबाव में नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह तर्क तर्कहीन है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किया, तो एम स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के प्रभाव में नहीं था; वास्तव में, मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में भी अपनी राय दर्ज की।

बी.

सी.

डी.

ई.

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि निचली अदालतें यह नहीं समझने में गलती कर गई कि अभियोजन पक्ष पीड़ित की उम्र के संबंध में सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा। पाँक्सो अधिनियम की धारा 34 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद "जेजे अधिनियम") की धारा 94 का संदर्भ यह कहने के लिए दिया गया था कि आयु निर्धारण तय किए गए वैधानिक मानदंडों के आधार पर होना चाहिए। सबसे पहले, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या मैट्रिक का प्रमाण पत्र देखना पड़ता था; यदि वह उपलब्ध नहीं था, तो स्थानीय या नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड पर विचार किया जाना चाहिए, और यदि दस्तावेजों के पहले दो वर्गों में से

कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो आयु निर्धारण ऑसिफिकेशन टेस्ट पर निर्भर करता है। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान मामले में, अस्थिकरण परीक्षण ने संकेत दिया कि एम की आयु 18 और 20 के बीच थी, जिससे साबित होता है कि वह नाबालिग नहीं थी। इस पहलू को पीडब्लू-9 द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, जिसने परीक्षण रिपोर्ट भी तैयार की थी।

एफ.

जी.

एच.

484

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

9. हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि पीड़ित की उम्र 18 वर्ष से कम थी। यह तर्क दिया गया कि इन परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए और यह कि पीड़ित ने अपना बयान बदल दिया था और आई. डी. 1 की धारा 164 के तहत अपने बयान में जो कहा था, उसके विपरीत बयान दिया था, अपीलार्थी को उन अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 366 के तहत आरोप से बरी कर दिया जो पीड़ित के अपहरण या जबरन अपहरण के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से झूठ बताता है।

बी.

10. श्री वी. कृष्णमूर्ति, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज समवर्ती दोषसिद्धि और सजा का समर्थन किया; उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही पीड़ित और अपीलकर्ता एक-दूसरे को जानते थे, और भले ही यह स्वीकार किया गया था कि उनकी एक-दूसरे के लिए भावनाएँ थीं, तथ्य यह है कि पीड़ित वैधानिक आयु से कम था, और सहमति अप्रासंगिक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीड़ित की उम्र के संबंध में नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्षों का समर्थन या पुष्टि केवल उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका डी. डब्ल्यू.-2 की गवाही से की गई थी, जहाँ एम. ने पढ़ाई की थी। उसने अपदस्थ कर दिया था कि स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, एम की जन्म तिथि 11.07.1997 है।

सी.

डी.

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. इस मामले में दलीलों और साक्ष्य के गुण-दोष पर चर्चा करने से पहले, पाँक्सो अधिनियम की धारा 34 को निकालना आवश्यक है जो इस प्रकार है:

ई.

“34. बालक द्वारा अपराध किए जाने के मामले में प्रक्रिया और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण।- (1) जहाँ कोई अपराध हो।

इस अधिनियम के तहत एक बच्चे द्वारा प्रतिबद्ध है, ऐसे बच्चे के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के प्रावधानों के तहत व्यवहार किया जाएगा।

एफ.

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो ऐसा प्रश्न विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद निर्धारित किया जाएगा और वह ऐसे निर्धारण के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

जी.

(3) विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं समझा जाएगा कि उप-धारा (2) के तहत उसके द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी।”

एच.

485

पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

12. पाँक्सो अधिनियम की धारा 34 (1) को ध्यान में रखते हुए, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 प्रासंगिक और लागू हो जाती है। उस प्रावधान को नीचे निकाला गया है:

“94. आयु का अनुमान और निर्धारण।- (1) जहाँ समिति या बोर्ड को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके सामने लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, समिति या बोर्ड बच्चे की उम्र को लगभग बताते हुए ऐसी टिप्पणी दर्ज करेगा और उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 14 या धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ेगा।

बी.

सी.

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा -

डी.

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में; (ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

ई.

(iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा:

एफ.

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण परीक्षा ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।”

जी.

13. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पाँक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित होने के संदर्भ में किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर अदालतों को जेजे अधिनियम की धारा 94 में बताए गए कदमों का सहारा लेना पड़ता है।

एच.

486

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

किशोर न्याय अधिनियम में जिन तीन दस्तावेजों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि संबंधित न्यायालय को निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार करके आयु निर्धारित करनी होगी:

“(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में; (ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

बी.

(iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

सी.

14. जेजे अधिनियम की धारा 94 (2) (iii) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके अभाव में निगम या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और इसके बाद ही ऐसे दस्तावेजों के अभाव में उम्र का निर्धारण "एक डी.

ऑसिफिकेशन टेस्ट "या" कोई अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण "

संबंधित प्राधिकारी, अर्थात् समिति या बोर्ड या न्यायालय के आदेशों पर संचालित।वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विचार किया गया था, न कि जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र पर।Ex. सी1, यानी स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र में पीड़ित की जन्म तिथि 11.07.1997 के रूप में दिखाई गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं बल्कि अदालत द्वारा गवाह, यानी सी. डब्ल्यू.-1 को तलब किया गया था।अभियोजन पक्ष पर हमेशा यह स्थापित करने का भार होता है कि वह क्या आरोप लगाता है; इसलिए, अभियोजन पक्ष को उस दस्तावेज़ पर वापस नहीं किया जा सकता था जिस पर उसने कभी भरोसा नहीं किया था।इसके अलावा, संबंधित राजस्व अधिकारी (उप तहसीलदार) डी. डब्ल्यू.-3 ने शपथ लेते हुए कहा था कि जन्म और मृत्यु के संबंध में वर्ष 1997 के रिकॉर्ड गायब थे।चूंकि यह धारा 94 (2) (i) में उल्लिखित दस्तावेजों के किसी भी वर्ग के विवरण का जवाब नहीं देता था क्योंकि यह केवल एक हस्तांतरण प्रमाण पत्र था, इसलिए पूर्व सी-1 पर यह मानने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि अपराध के समय एम की आयु 18 वर्ष से कम थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

487

पी. युवप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

15. हाल के एक निर्णय में, ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश और अन्य, 3 इस न्यायालय ने उन मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित किया जहां आयु निर्धारण की आवश्यकता होती है। न्यायालय जे. जे. अधिनियम की धारा 94 के साथ पूर्ववर्ती किशोर न्याय नियमों (जो समान सामग्री में है) के नियम 12 पर विचार कर रहा था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“20. जेजे नियम, 2007 का नियम 12 आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। कानून के साथ संघर्ष में किसी व्यक्ति की किशोरता का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति, या यदि उपलब्ध हो तो दस्तावेजों के आधार पर किया जाना था। लेकिन न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा आयु के निर्धारण की जांच साक्ष्य प्राप्त करके की गई थी: (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और जिसके अभाव में; (ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुआ; और जिसके अभाव में; (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। केवल उपरोक्त (i), (ii) और (iii) में से किसी एक की अनुपस्थिति में, किशोर या बच्चे की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जा सकती है। यह भी प्रावधान किया गया था कि जब निर्धारण किया जा रहा था, तो एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम उम्र पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दिया जा सकता था।”

बी.

सी.

डी.

ई.

16. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बोलते हुए, विशेष रूप से जेजे अधिनियम की धारा 94 (2) में विभिन्न विकल्पों के बारे में, इस अदालत ने कहा

संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 4 कि: “धारा 94 (2) का खंड (i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख और संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को उसी श्रेणी (अर्थात् (i) में रखता है। इसके अभाव में श्रेणी (ii) में निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान है। यह केवल (i) और (ii)

की अनुपस्थिति में है कि आयु निर्धारण चिकित्सा विश्लेषण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। धारा 94 (2) (ए) (आई) उन प्रावधानों पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है जो 2000 के अधिनियम के तहत बनाए गए 2007 के नियमों के नियम 12 (3) (ए) में निहित थे। नियम 12 (3) (ए) (आई) के तहत मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र था

एफ.

जी.

3 2021 (12) एससीआर 502 4 [2019] 9 एससीआर 735

एच.

488 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

वरीयता दी गई और यह केवल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में था कि पहली बार उपस्थित होने वाले स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख प्राप्त की जा सकती थी। धारा 94 (2) (i) में स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख के साथ-साथ मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है।

बी.

17. अबुज़र हुसैन @गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम राज्य

बंगाल 5, इस अदालत ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि यह साबित करने का भार कि कोई किशोर (या निर्धारित आयु से कम) है, यह दावा करने वाले व्यक्ति पर है। इसके अलावा, उस निर्णय में, अदालत ने उन दस्तावेजों के पदानुक्रम का संकेत दिया जिन्हें वरीयता के क्रम में स्वीकार किया जाएगा। 18. इस मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, एम के स्कूल, सी. डब्ल्यू.-1 के प्रधानाध्यापक को अदालत द्वारा तलब किया गया और एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Ex.C-1) प्रस्तुत किया गया। इस गवाह ने एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र रजिस्टर प्रस्तुत किया जिसमें एम का नाम था। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उसने एक वर्ष के लिए स्कूल में पढ़ाई की थी, यानी 2009-10 और जन्म तिथि उस स्कूल द्वारा दिए गए रिकॉर्ड शीट के आधार पर थी जहां उसने 7 वीं कक्षा में पढ़ाई की थी।

चिन्नासोआलिपलायम पंचायत स्कूल के प्रधानाध्यापक डी. डब्ल्यू.-2 टी. एम. टी. पूंगोथोई ने अदालत द्वारा भेजे गए समन का जवाब दिया और कहा कि 'एम' ने 03.04.2002 से उनके स्कूल में दाखिला लिया था और उनकी जन्म तिथि 11.07.1997 के रूप में दर्ज की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र पर आधारित थी, लेकिन इसे आम तौर पर कुंडली के आधार पर दर्ज किया जाता था। उन्होंने स्वीकार किया कि जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज़ किस आधार पर दर्ज किया गया था, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसी मुद्दे पर पहले कहा गया है, यानी जन्म तिथि, थिरु प्रकाशम, डी. डब्ल्यू.-3 में

कहा गया है कि वर्ष 1997 से संबंधित जन्म रजिस्टर उनके कार्यालय के अभिलेख कक्ष में उपलब्ध नहीं था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

19. उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज ने "जन्म तिथि" के विवरण का उत्तर नहीं दिया।

स्कूल से प्रमाण पत्र "या" मैट्रिक या समकक्ष

संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्रमाण पत्र या निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के लिए स्वीकार्य चिकित्सा परीक्षणों/जांच के माध्यम से यह साबित करना अनिवार्य था कि पीड़ित की आयु जेजे Act.PW-9 की धारा 94 (2) (iii) के अनुसार 18 वर्ष से कम थी, वेल्लोर के सामान्य अस्पताल में मुख्य सिविल डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. थेनमोझी ने एक्स-रे प्रस्तुत किया।

जी.

5 [2012] 9 एससीआर 224 ए

एच.

489

पी. युवप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

रिपोर्ट और अपदस्थ किया कि एम की परीक्षा के संदर्भ में, एक प्रमाण पत्र

यह कहते हुए जारी किया गया था कि उक्त लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम होगी। जिरह में, वह

उन्होंने स्वीकार किया कि एम की आयु को 19 वर्ष के रूप में लिया जा सकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "जब की सटीक तारीख

जन्म स्कूल के अभिलेखों से उपलब्ध है, चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अनुमानित अनुमानित आयु निर्धारित नहीं की जा सकती है

बी.

कारक "।यह निष्कर्ष, इस अदालत के माने गए दृष्टिकोण में, गलत और गलत है।जैसा कि पहले कहा गया था, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रवेश रजिस्टर के उद्धरण, वे नहीं हैं जो धारा 94 (2) (i) अनिवार्य करती है; और न ही वे धारा 94 (2) (ii) के अनुरूप हैं क्योंकि डी. डब्ल्यू.-1 ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि पीड़ित के जन्म से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं थे, एम. इन परिस्थितियों में, जेजे अधिनियम की धारा 94 के साथ दिया गया एकमात्र साक्ष्य चिकित्सा अस्थीकरण परीक्षण था, जो पीड़ित के कई एक्स-रे के आधार पर था, और जिसके आधार पर पीडब्लू-9 ने अपना बयान दिया था।उसने पीड़ित की हड्डियों की जांच, उनके विकास के चरण के बारे में विस्तार से बताया और राय दी कि वह 18-20 वर्ष के बीच थी; प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि उम्र 19 वर्ष हो सकती है।

अभियोजन साक्षी-इअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-खअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-एअभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-इअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ा अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ैअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-ऑअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-फअभियोजन साक्षी-ि अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-शअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी-णअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-णअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-णअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ी

अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-टअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी-चअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी-ॉअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-् अभियोजन साक्षी-टअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-् अभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-9 अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-ा अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-गअभियोजन साक्षी-ईअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-।अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-2 अभियोजन साक्षी-0 अभियोजन साक्षी-.अभियोजन साक्षी-इस मामले में, अपीलार्थी पर अन्य बातों के साथ-साथ पाँक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। धारा 6 के तहत अपराध इस सबूत पर निर्भर करता है कि "यौन हमला" हुआ था। उस शब्द को धारा 7 द्वारा परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

सी.

डी.

ई.

“जो कोई भी यौन इरादे से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है या बच्चे को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है, या यौन इरादे से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें बिना प्रवेश के शारीरिक संपर्क शामिल होता है, उसे यौन हमला कहा जाता है।”

एफ.

संबंधित समय पर धारा 6 के तहत अपराध को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

जी.

“जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।”

धारा 3 भेदक यौन हमले को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

एच.

“3. भेदक यौन हमला।- एक व्यक्ति को "भेदक यौन हमला" करने के लिए कहा जाता है यदि -

(क) वह अपने लिंग को किसी भी हद तक बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या बी.

(बी)।

(सी)।

(घ) "।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (ए) में प्रावधान है कि 'उग्र भेदक यौन हमले' का वही अर्थ है जो धारा 5 में दिया गया है। इसलिए, धारा 5, जो 'उग्र भेदक यौन हमले' को परिभाषित करती है, प्रासंगिक है। धारा 5 (1) इस प्रकार है:

सी.

“5. उग्र भेदक यौन हमला।- (अ)

डी.

(एल) जो कोई भी बच्चे पर एक से अधिक बार या बार-बार यौन हमला करता है; या धारा 4, सुसंगत समय पर, निम्नानुसार है:

“(1) जो कोई भी भेदक यौन हमला करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।”

ई.

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 351 में "हमला" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

“जो कोई भी कोई इशारा करता है, या कोई भी तैयारी करने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि इस तरह के इशारे या तैयारी से उपस्थित किसी भी व्यक्ति को यह आशंका होगी कि जो वह इशारा या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति के लिए आपराधिक बल का उपयोग करने वाला है, उसे हमला करने के लिए कहा जाता है।”

एफ.

"आपराधिक बल" अभिव्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 350 द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

जी.

“जो कोई भी जानबूझकर किसी व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, किसी अपराध को करने के लिए बल का उपयोग करता है, या इस तरह के बल का उपयोग करने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि इस तरह के बल के उपयोग से वह चोट पहुंचा सकता है, ए

एच.

491

पी. युवप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिस व्यक्ति के लिए बल का उपयोग किया जाता है, उसके लिए डर या झुंझलाहट, उस दूसरे के लिए आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए कहा जाता है।”

21. Cr.PC की धारा 164 के तहत अपने बयान में, पीड़ित एम ने बयान दिया था कि वह अपीलार्थी से प्यार करती थी, उसने जहर खा लिया था, और यहां तक कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि वह अपीलार्थी के साथ रहने के लिए दृढ़ थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपने बयान से मुकर गई। फिर भी, चिकित्सीय साक्ष्य (पीडब्लू-11, डॉ. कविता का बयान) ने संकेत दिया कि पीड़ित को एक टूटा हुआ हाइमेन था; उसके निजी शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी।

बी.

भागों, और कि उसके अनुसार "चिकित्सा परीक्षा से 48 घंटे पहले यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसने यौन उत्पीड़न किया था

मेरे द्वारा दी गई राय।” इस गवाह ने अपने परीक्षण के नोट्स भी प्रस्तुत किए (उदा. पी-11)। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की राय है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि अपीलार्थी की ओर से जबरदस्ती या मजबूरी के परिणामस्वरूप कोई भेदक यौन हमला हुआ था। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी सजा को कम करते हुए इसे मान्यता दी (क्योंकि उसकी राय में, एम उस समय नाबालिग था),

सी.

यह देखते हुए कि "पी. डब्ल्यू. 3 प्रेम विफलता के कारण आत्महत्या करने के लिए जहर लेने की हद तक चला गया था, भारी दबाव में, वह पी. डब्ल्यू. 3 के साथ गया था, उससे शादी की और उसके साथ यौन संबंध बनाए, दोनों शादी से पहले और शादी के बाद भी।

डी.

शादी।" इन तथ्यों और पॉक्सो अधिनियम के तहत परिभाषाओं, विशेष रूप से "यौन हमले" की परिभाषाओं, धारा 5 और 6, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 350 और 351 के साथ पढ़ा जाता है, से यह देखा जा सकता है कि यह केवल तभी होता है जब भेदक यौन हमला होता है, जिसका अर्थ है नाबालिग पीड़िता की सहमति के साथ या उसके बिना यौन संपर्क, कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध किए जाते हैं।

ई.

22. इस मामले में साबित हुए सभी तथ्य स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के साथ जाने और यहां तक कि उनकी शादी का जश्न मनाने के लिए एम की इच्छा का संकेत देते हैं। हालाँकि, उन्होंने धारा 164 Cr.PC के तहत बयान का समर्थन नहीं किया। उस बयान को पूरी तरह से खारिज करने के लिए, निचली अदालत ने कहा कि:

एफ.

"इस मामले में, P.W.-16 के निरीक्षक के आदेश पर लड़की एम 6 को न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, इरोड के समक्ष पेश किया गया था और उसने स्वेच्छा से यू/एस बयान दिया है। 164 Cr.PC. यह साबित करने के लिए कि उपरोक्त बयान किसी मजबूरी में नहीं दिया गया था, इस अदालत के समक्ष कोई सबूत नहीं रखा गया है।"

जी.

6 नाम बदला गया।

एच.

492

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

निचली अदालत का उपरोक्त अनुमान असमर्थनीय है। अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को पेश नहीं किया जिसने बयान दर्ज किया; हालाँकि, वह अधिकारी उपलब्ध था और इरोड में तैनात था। उसने मुकदमे के दौरान डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में गवाही दी, और महत्वपूर्ण रूप से पीड़ित के बयान की सत्यता की पुष्टि की। पी-4) निम्नानुसार बताते हुए:

"यह उक्त लड़की द्वारा जानबूझकर दिया गया एक सच्चा बयान है। उक्त बयान मजबूरी में नहीं दिया गया था। यह सही है अगर यह कहा जाए कि (एम) ने अपने बयान में मुझसे कहा था

कि मैं और मेरे पड़ोसी, जो पास के घर में थे, युवप्रकाश नाम से पिछले डेढ़ साल से प्यार करते हैं, हम अक्सर फोन पर एक-दूसरे से बात करते थे, मुझे फोन पर बात करते देख मेरी दादी ने मेरे पिता को बताया था, मैंने चींटियों के लिए कीटनाशक लिया था और आत्महत्या करने का प्रयास किया था।”

बी.

सी.

अभियोजन पक्ष ने इस गवाह से जिरह भी नहीं की। इन समग्र कारकों को ध्यान में रखते हुए, अदालत की राय है कि Cr.PC की धारा 164 के तहत M के बयान में घटनाओं का एक सच्चा वर्णन है। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब था कि उस पर कोई भेदक यौन हमला नहीं हुआ था। इसलिए, पाँक्सो अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे। विवादित फैसले में अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 366 के तहत आरोप को खारिज कर दिया गया। पाँक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ-साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत उनके खिलाफ आरोपों को कायम नहीं रखा जा सकता है; इसलिए, निचली अदालतों के निष्कर्ष, यानी दोषसिद्धि और लगाए गए दंड को दरकिनार कर दिया जाता है।

डी.

ई.

23. पूर्वगामी विश्लेषण और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की राय है कि अपीलार्थी उन अपराधों का दोषी नहीं है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था; वह इसके द्वारा बरी हो जाता है। विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है; अपीलार्थी को तब तक तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में इसकी आवश्यकता न हो। अपील की अनुमति दी जाती है, लेकिन लागत पर कोई आदेश नहीं।

एफ.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

एच.